STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of recommendation contained in Seventh Report of the Department - related Parliamentary Standing Committee on, Consumer Affairs Food and Public Distribution

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Sir, I am making this statement on the status of implementation of recommendations contained in the Seventh Report of the Standing Committee on Food and Consumer Affairs and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in pursuance of direction under Rule 266 of the hon. Chairman of Rajya Sabha issued vide Rajya Sabha Bulletin Part II dated 28.9.2004.

A statement indicating the Action Taken/status of all the recommendations contained in the Seventh Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution is annexed. It may be noted that the report contains 21 recommendations. These recommendations have been carefully examined by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs). All the recommendations have been accepted and action taken thereon has been indicated.

The Action Taken replies had been sent to the Rajya Sabha on 26.07.2005. This was presented by the Chairman of the Standing Committee to the Rajya Sabha on 01.12.2005 and laid on the Table of the Rajya Sabha on the same day.

Status of implementation of recommendations contained in the Sixth and Tenth Reports of Department - related Parliamentary Standing Committee on Agriculture

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Sir, I am making this statement on the status of implementation of recommendations contained in the Sixth and Tenth Reports of the Standing Committee on Agriculture in pursuance of the provisions of Rule 266 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States issued vide Rajya Sabha Bulletin Part-II, dated September 28, 2004.

The Standing Committee on Agriculture examined the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture, Department of Agricultural Research

and Education (DARE) for the year 2004-05 and presented their Sixth report, based on the Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the Second Report of the Standing Cornmittee on Agriculture (2004-05). This Report was presented to the Lok Sabha on 2nd March, 2005, and the same was laid in the Rajya Sabha on the same day. The Committee have accepted the Replies of the Government to their Recommendation Nos. 1,2,3,5,7 and 10 of the Second Report. The Committee did not accept the Replies of the Government to their Recommendation Nos. 4,8,9 and 11. Further, the Committee still await the final Reply of the Government to their Recommendation No.6. Hence, the Department has furnished the Further Replies of the Government to all these Recommendations in the Action Taken Report.

THE BUDGET (GENERAL) 2006-2007 - *Contd.*

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, अभी आदरणीय सदस्या प्रभा ठाकुर जी अपने भाषण में भारत का अभी जो आणविक समझौता हुआ है, उसके बारे में बहुत बातें कर रही थीं। एक तरफ राजनीतिक संदेश इस बजट भाषण में देने की कोशिश का उल्लेख आया है, लेकिन मैं केवल एक ही बात बताना चाहूंगा कि परसों का "टाइम्स ऑफ इंडिया" आप देख लें, आपके ही वामपंथी पार्टनर श्री कारत का स्टेटमेंट है कि UPA turning India into junior partner of United States. जिनकी बैसाखियों पर आपकी सरकार चल रही है, वे इसको लेकर क्या कह रहे हैं, और माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की शुरुआत में जो राजनीतिक संदेश की बात आपने की है, उससे स्पष्ट है कि किस प्रकार का राजनीतिक संदेश है। डिसइन्वेस्टमेंट का क्या हुआ? एयरपोर्ट के प्राइवेटाइज़ेशन पर वामपंथियों का क्या रुख रहा? क्या साझा न्यूनतम कार्यक्रम का यह राजनीतिक संदेश आप दे रहे हैं? कल इसके बारे में माननीय यशवंत सिन्हा जी ने कहा, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सीधे अपनी बात पर आता हूं कि यह सरकार बार-बार जी.डी.पी. 8.1 परसेंट की बात कर रही है लेकिन यह कोई एक दिन में नहीं आया, जैसा कल यशवंत सिन्हा जी ने बताया है और आपने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। आप आर्थिक समीक्षा के पहले ही पेज पर देख लें कि आपने इस बात को स्वीकार किया है कि अर्थव्यवस्था द्वारा सतत् कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की 8 प्रतिशत से अधिक की अभिवृद्धि प्रलेखित इतिहास के केवल पांच वर्षों में हासिल की गई है और इन पांच वर्षों में से दो वर्ष पिछले तीन वर्ष के हैं। अपनी आर्थिक समीक्षा में आप इस बात को स्वीकार कर रहे हो? जब सारे आंकड़े देखें, तो 7.5 परसेंट जी.डी.पी. पिछली सरकार के द्वारा छोड़ा हुआ था, यदि आप 8.1 परसेंट की बात करते हैं, तो आपका योगदान तो 0.6 परसेंट बैठता है और उसके लिए आप इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही इसमें एक बात और जो आगे कही गई है, कहा गया है कि इसमें 2.3 प्रतिशत की वृद्धि खाद्यान्न उत्पादन में 5 मिलियन टन की अभिवृद्धि होने की आशा है। माननीय उपसभापति जी, क्षमा करें, मुझे इसमें थोड़ा संदेह है। आप आर्थिक समीक्षा के पेज 14-15 के आंकड़े देख लें, ये आंकड़े जो आपने पिछले समय के दिए हैं, उत्पादन - आप इसमें देखें कि कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2003-04 में 213 मीट्रिक